बुधवार, 19 अगस्त, 2026

www.tvbharatvarsh.in

E-PAPER

कुल पृष्ठ–08

ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में 100 सिक्स लगाने वाले , भारत के पहले बल्लेबाज बन गए

Page-04

# भारतवर्ष

सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

तृषा विवाद पर DMK का विजय पर हमला

Page-05

CJI सूर्यकांत का स्पष्टीकरण, कहा- निमंत्रण कभी स्वीकार नहीं किया

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने हैदराबाद स्थित नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ (NALSAR) के दीक्षांत समारोह को लेकर सामने आए विवाद पर स्थिति साफ कर दी है। CJI सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि उन्होंने विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने का निमंत्रण कभी स्वीकार ही नहीं किया था। ऐसे में कार्यक्रम में उनके जाने और छात्रों के विरोध का सामना करने से जुड़ी खबरों या अटकलों का कोई आधार नहीं है।जोधपुर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के कुलपतियों से बातचीत के दौरान CJI सूर्यकांत ने इस पूरे मामले पर अपनी स्थिति स्पष्ट की। अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने बताया कि NALSAR की ओर से दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए निमंत्रण मिला था, लेकिन उन्होंने शुरुआत में ही इसमें शामिल होने पर सहमति नहीं दी थी। इसके बावजूद पिछले कुछ दिनों से इस कार्यक्रम को लेकर अलग-अलग तरह की चर्चाएं और दावे सामने आ रहे थे।विवाद का केंद्र यह खबर बनी हुई थी कि CJI सूर्यकांत NALSAR के दीक्षांत समारोह में शामिल होने वाले थे और छात्रों की ओर से उनके विरोध की संभावना थी। कुछ रिपोर्टों और चर्चाओं के बाद यह मामला सार्वजनिक बहस का विषय बन गया था। हालांकि, अब CJI के स्पष्टीकरण के बाद यह साफ हो गया है कि उन्होंने कार्यक्रम में शामिल होने की सहमति ही नहीं दी थी।

## जंतर-मंतर प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस का जवाब

## 30 हजार की भीड़ और हिंसा का दिया हवाला

दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर NEET पेपर लीक के विरोध में हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों को खारिज कर दिया है। पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में कहा कि प्रदर्शन के दौरान स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई थी और बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी के कारण भीड़ को नियंत्रित करना चुनौतीपूर्ण हो गया था।पुलिस के मुताबिक, प्रदर्शन में करीब 30 हजार से अधिक लोग शामिल हुए थे। प्रदर्शनकारियों की भीड़ जब निर्धारित क्षेत्र से आगे बढ़ने लगी और बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश की गई, तब स्थिति बिगड़ गई। पुलिस का दावा है कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर हिंसा का सहारा लिया और सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी भी की। इसके बाद भीड़ को नियंत्रित करने के लिए क्रमबद्ध तरीके से बल का इस्तेमाल किया गया।दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई आवश्यक थी। पुलिस के अनुसार, बल प्रयोग अचानक या बिना कारण नहीं किया गया, बल्कि स्थिति के अनुसार चरणबद्ध तरीके से कदम उठाए गए। पुलिस ने अपने हलफनामे में यह भी कहा कि बड़ी भीड़ के अनियंत्रित होने की स्थिति में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना जरूरी था।यह मामला 20 जुलाई को हुए छात्र आंदोलन से जुड़ा है, जिसका नेतृत्व कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP ने किया था। छात्र NEET परीक्षा में कथित पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी शामिल थी।प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच झड़प की खबरें सामने आई थीं। सोशल मीडिया पर कई वीडियो भी वायरल हुए थे, जिनमें पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की दिखाई गई थी। इसके बाद पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठे और कुछ याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गईं।सुप्रीम कोर्ट इस मामले में छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज FIR और पुलिस कार्रवाई से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। अदालत ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए हाई-पावर कमेटी गठित करने की इच्छा भी जताई है, जिसमें पूर्व न्यायाधीश और सेवानिवृत्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हो सकते हैं।अब दिल्ली पुलिस के जवाब के बाद इस मामले में अदालत की आगे की सुनवाई महत्वपूर्ण होगी। एक तरफ पुलिस अपने बल प्रयोग को परिस्थितियों के अनुरूप बता रही है, वहीं प्रदर्शनकारी पक्ष पुलिस कार्रवाई की स्वतंत्र जांच की मांग कर रहा है।

बच्चियों के डांस से विवाद, जायरा वसीम ने वक्फ बोर्ड पर उठाए सवाल

जम्मू-कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान बच्चियों के डांस का एक वीडियो सामने आने के बाद पूर्व अभिनेत्री जायरा वसीम ने इस कार्यक्रम को लेकर सवाल खड़े किए हैं। जायरा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड की भूमिका पर आपत्ति जताई और पूछा कि धार्मिक एवं सामुदायिक उद्देश्यों के लिए गठित संस्था के कार्यक्रम में छोटी बच्चियों को मंच पर नृत्य कराने की जरूरत क्यों पड़ी।वायरल वीडियो में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान कुछ बच्चियां मंच पर नृत्य करती दिखाई दे रही हैं। वीडियो सामने आने के बाद इस पर सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। इसी बीच जायरा वसीम ने भी इस कार्यक्रम और इसके आयोजन को लेकर अपनी राय सामने रखी। जायरा ने सवाल उठाते हुए कहा कि बच्चों को केवल नृत्य या मनोरंजन तक सीमित करने के बजाय उन्हें शिक्षा, सोचने, सीखने, रचनात्मक गतिविधियों और समाज में योगदान देने के अवसर दिए जाने चाहिए। उन्होंने बच्चों की प्रतिभा के विकास और उनके भविष्य को लेकर व्यापक सोच की जरूरत पर जोर दिया। पूर्व अभिनेत्री की टिप्पणी इसलिए भी चर्चा में आ गई क्योंकि जायरा वसीम ने फिल्मी करियर छोड़ने के बाद सार्वजनिक जीवन और मनोरंजन जगत से काफी दूरी बना ली है। ऐसे में उनका किसी सार्वजनिक कार्यक्रम या सामाजिक मुद्दे पर टिप्पणी करना अक्सर चर्चा का विषय बन जाता है।

विधानसभा में मंत्री की चूक

## CM विजय ने मांगी माफी, करुणानिधि के सम्मान को लेकर विवाद

तमिलनाडु विधानसभा में मंगलवार को उस समय असामान्य स्थिति देखने को मिली, जब मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय को अपनी सरकार के एक मंत्री की ओर से हुई चूक के लिए सदन में सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी। मामला राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और द्रविड़ राजनीति के प्रमुख नेता दिवंगत एम. करुणानिधि के नाम के इस्तेमाल से जुड़ा था। विपक्षी दल डीएमके ने इस पर आपत्ति जताई, जिसके बाद मुख्यमंत्री विजय खुद सामने आए और स्थिति संभालने की कोशिश की।बताया गया कि विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सरकार के एक मंत्री ने करुणानिधि का नाम लेते समय उनके नाम के साथ औपचारिक और सम्मानजनक संबोधन का इस्तेमाल नहीं किया। डीएमके ने इसे पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता का अपमान बताते हुए सदन में कड़ा विरोध दर्ज कराया। मामला बढ़ता देख मुख्यमंत्री विजय ने हस्तक्षेप किया और मंत्री की ओर से हुई चूक पर माफी मांगी।मुख्यमंत्री के इस कदम को विधानसभा की गरिमा बनाए रखने की कोशिश के तौर पर देखा गया। विजय ने स्पष्ट किया कि करुणानिधि तमिलनाडु के लंबे राजनीतिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले नेता रहे हैं और उनके प्रति सम्मान बनाए रखना जरूरी है। मुख्यमंत्री की ओर से माफी मांगने के बाद सदन में उठे विवाद को शांत करने का प्रयास किया गया। इस घटनाक्रम का राजनीतिक महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति में करुणानिधि का प्रभाव बेहद व्यापक रहा है। वह कई बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे और डीएमके के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। उनके नाम और राजनीतिक विरासत को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में गहरी भावनात्मक जुड़ाव है। ऐसे में उनके नाम के साथ सम्मानजनक संबोधन न होने को डीएमके ने गंभीरता से लिया।मुख्यमंत्री विजय की राजनीति भी इस समय तमिलनाडु में तेजी से चर्चा में है। अभिनेता से राजनेता बने विजय ने अपनी पार्टी टीवीके के जरिए राज्य की राजनीति में अलग राजनीतिक विकल्प खड़ा करने की कोशिश की है। ऐसे में विधानसभा के भीतर उनकी सरकार के मंत्री की इस चूक और उसके बाद मुख्यमंत्री द्वारा खुद माफी मांगने की घटना पर राजनीतिक नजरें टिक गई हैं।फिलहाल मुख्यमंत्री की माफी के बाद मामला शांत होता दिखाई दे रहा है। हालांकि, इस घटना ने एक बार फिर तमिलनाडु की राजनीति में नेताओं के सम्मानजनक संबोधन और राजनीतिक मर्यादा को लेकर बहस छेड़ दी है।

## पिकअप-ट्रक की टक्कर में यूपी के 8 मजदूरों की मौत

मध्य प्रदेश के भिंड जिले में नेशनल हाईवे-719 पर देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में आठ प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 30 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसा उस समय हुआ जब मजदूरों से भरी एक लोडिंग पिकअप गाड़ी और सामने से आ रहे ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि पिकअप में सवार कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।बताया जा रहा है कि हादसे का शिकार हुए मजदूर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। वे धान की रोपाई का काम पूरा करने के बाद वापस अपने घर लौट रहे थे। मजदूरों का समूह एक लोडिंग पिकअप वाहन में सवार था। इसी दौरान नेशनल हाईवे-719 पर पिकअप और ट्रक की आमने-सामने टक्कर हो गईटक्कर के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं और घायलों को दुर्घटनाग्रस्त वाहन से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। हादसे में आठ मजदूरों की मौके पर ही या इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं। घायलों में कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। ऐसे में मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका भी जताई गई है।

महाराष्ट्र में नया धर्मांतरण कानून लागू

## जबरन धर्म परिवर्तन पर 7 साल तक की सजा

महाराष्ट्र सरकार ने धर्म परिवर्तन को लेकर एक नया कानूनी ढांचा तैयार किया है। सरकार की ओर से आधिकारिक गजट में अधिसूचना जारी किए जाने के बाद महाराष्ट्र धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम, 2026 को 28 अगस्त से लागू किया जाएगा। यह कानून राज्य में सभी धर्मों के लोगों पर लागू होगा और जबरन या धोखाधड़ी के जरिए कराए जाने वाले धर्म परिवर्तन पर सख्ती का प्रावधान करता है।नए कानून के तहत किसी व्यक्ति का जबरन धर्म परिवर्तन कराना अपराध माना जाएगा। इसके अलावा धोखाधड़ी, दबाव, अनुचित प्रभाव या किसी अन्य गलत तरीके का इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करने पर भी कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को सात साल तक की जेल की सजा हो सकती है।सरकार के मुताबिक, कानून का उद्देश्य लोगों को उनकी इच्छा के विरुद्ध धर्म परिवर्तन से बचाना है। नए प्रावधानों में धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया को लेकर भी कई नियम निर्धारित किए गए हैं। कानून का उल्लंघन करने वाले मामलों में पुलिस और प्रशासन को कार्रवाई का अधिकार दिया गया है।जबरन धर्म परिवर्तन के मामलों को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है और इसके लिए गैर-जमानती प्रावधान का भी उल्लेख किया गया है। इसका मतलब है कि आरोपी को मामले की जांच और न्यायिक प्रक्रिया के दौरान आसानी से जमानत नहीं मिल सकेगी। सरकार का दावा है कि इससे दबाव, लालच या धोखे के जरिए होने वाले धर्म परिवर्तन पर प्रभावी रोक लगाने में मदद मिलेगी।

# SAVE America Act पर जोर

# भारत की चुनाव व्यवस्था से प्रभावित ट्रंप

**सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच हुए मक्का संयुक्त रक्षा समझौते के तुरंत बाद जाज़ान में अरामको रिफाइनरी पर हूथी हमला हुआ।समझौते में एक देश पर सशस्त्र हमला तीनों देशों पर हमला माने जाने की बात कही गई है, लेकिन हमले के बाद कोई संयुक्त सैन्य प्रतिक्रिया नहीं दिखी।ऐसे में सवाल उठ रहा है कि यह समझौता वास्तव में सामूहिक सुरक्षा की गारंटी है या अभी केवल रक्षा सहयोग का एक ढांचा है।**

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की चुनाव व्यवस्था से काफी प्रभावित नजर आ रहे हैं। उन्होंने भारत जैसी चुनाव व्यवस्था लागू करने के लिए Save America Act पर जोर दिया है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में भारतीय चुनाव व्यवस्था का जिक्र किया है। इस संबंध में उन्होंने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ हुई बातचीत का उल्लेख किया और अमेरिका में मतदाता पहचान संबंधी नियमों को सख्त करने पर जोर दिया। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर कहा कि इसी महीने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने उनके प्रशासन से सवाल किया था कि अमेरिका में वैध फोटो पहचान पत्र के बिना चुनाव कैसे कराए जाते हैं? भारत के पिछले लोकसभा चुनाव में करीब 64.6 करोड़ वोटर थे और एक प्रतिशत से भी कम लोगों ने डाक के जरिए वोट डाला। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में हर मतदाता के लिए वैध फोटो पहचान दस्तावेज जरूरी था। इन आंकड़ों का हवाला देते हुए ट्रंप ने कहा कि Save America Act को पास कराना जरूरी हो गया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक सेफगार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी (SAVE) America Act के तहत अमेरिका के चुनावी सिस्टम में बड़े बदलाव का प्रस्ताव है। यह प्रस्तावित कानून यह पक्का करना चाहता है कि सिर्फ़ अमेरिका के नागरिक ही फ़ेडरल चुनावों में वोट दे सकें। यह कानून अमेरिकी नागरिकों के लिए वोटर रजिस्ट्रेशन के समय नागरिकता का सबूत दिखाना अनिवार्य करेगा। इसके साथ ही पूरे देश में मतदाता पहचान पत्र की व्यवस्था को लागू करेगा। प्रस्तावित कानून मेल के जरिए वोटिंग पर भी सख्ती करेगा, जबकि बीमार, विकलांग, सेना में सेवारत या यात्रा करने वाले लोगों के लिए कुछ छूट देगा। इसके अलावा, राज्यों को गैर-नागरिकों की पहचान करके उन्हें वोटर रोल से हटाना होगा। इससे चुनावी धोखाधड़ी रोकने में मदद मिलेगी। इस एक्ट का मुख्य मकसद है कि सिर्फ़ अमेरिकी नागरिकों को ही अमेरिकी चुनावों का फ़ैसला करना चाहिए।भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने भी डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल सही हैं! भारत के पिछले चुनाव में 646 मिलियन वोटर्स में से हर एक को ID की ज़रूरत थी। कांग्रेस को SAVE अमेरिका एक्ट पास करना चाहिए। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी की भी तारीफ कर चुके हैं। मई महीने में दिल्ली में US इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के दौरान भारत में US के राजदूत Sergio Gor ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया। इस दौरान हुई बातचीत में ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि PM मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं नरेंद्र मोदी का बड़ा प्रशंसक हूं। भारत मुझ पर 100% भरोसा कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप भारतीय चुनाव व्यवस्था का उदाहरण देते हुए अब Save America Act पास कराने पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और ट्रंप प्रशासन से हुई बातचीत का जिक्र करते हुए ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट किया है।

## रिटायर गोरखा सैनिकों ने भारत का झंडा लहराया और भारत का राष्ट्रगान जन गण मन भी गाया

नेपाल के गोरखा सैनिक दशकों से भारतीय सेना का हिस्सा रहे हैं। भारतीय सेना में गोरखा रेजिमेंट है और इसमें नेपाल दिलेर गोरखा सैनिकों की भर्ती होती रही है। अग्निपथ योजना आने के आने के बाद गोरखा सैनिकों की भर्ती रुकी हुई है। नेपाली अब भी भारतीय सेना में भर्ती होना चाहते हैं और इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय सेना प्रमुख धीरज सेठ इस समय नेपाल पहुंचे हुए हैं। इस बीच नेपाल के पोखरा से गोरखा राइफल के रिटायर हुए सैनिकों का एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर शेयर किया जा रहा है। यह वीडियो नेपाल के पोखरा का बताया जा रहा है जहां पर रिटायर गोरखा सैनिकों ने भारत का झंडा लहराया और भारत का राष्ट्रगान जन गण मन भी गाया। नेपाल के नागरिक होने के बाद भारतीय झंडे को सलामी देना सोशल मीडिया में काफी पसंद किया जा रहा है। माना जा रहा है कि यह वीडियो स्वतंत्रता दिवस का है लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। नेपाल के भारतीय सेना के हिस्सा रहे गोरखा सैनिक भारती झंडे को सम्मान दे रहे हैं। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर कारगिल युद्ध लड़ चुके शौर्य चक्र से सम्मानित मेजर राकेश ने एक्स पर शेयर किया है। इस वीडियो की जमकर तारीफ की जा रही है। असल में साल 1947 में भारत, नेपाल और ब्रिटेन के बीच एक त्रिपक्षीय संधि हुई थी। इसके बाद से नेपाली गोरखा सैनिक भारतीय सेना में शामिल होते रहे हैं। हाल ही में नेपाल के पोखरा में गोरखा जवानों ने भारतीय सेना में भर्ती के लिए प्रदर्शन किया है। भारतीय सेना प्रमुख और नेपाली सेना प्रमुख के बीच मुलाकात हुई है। माना जा रहा है कि इसमें गोरखा सैनिकों की भर्ती का मुद्दा भी उठा है। नेपाली अब अग्निपथ योजना के तहत भी भर्ती होने के लिए तैयार हैं।

## इंदौर में सड़क फाड़कर निकला पानी डर कर पीछे हट गए राहगीर

## कल्पेश्वर महादेव मंदिर के पास ज़बरदस्त भूस्खलन हुआ

चमोली में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच पंच केदारों में पांचवें केदार के रूप में प्रसिद्ध कल्पेश्वर महादेव मंदिर के ऊपर भूस्खलन होने से मंदिर परिसर में भारी मात्रा में मलबा आ गया। देर रात हुई तेज बारिश के कारण मंदिर के ऊपर की पहाड़ी से अचानक भूस्खलन हुआ, जिससे मंदिर के आसपास के क्षेत्र में नुकसान हुआ है। भूस्खलन के चलते पहाड़ी से मलबा और पत्थर मंदिर परिसर के आसपास आ गिरे। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और मंदिर परिसर में जमा मलबे को हटाने तथा स्थिति को सामान्य करने में जुट गए। लगातार हो रही बारिश के कारण चमोली जिले के पर्वतीय क्षेत्रों में जगह-जगह भूस्खलन और अन्य नुकसान की घटनाएं सामने आ रही हैं। कल्पेश्वर महादेव मंदिर में हुए भूस्खलन से स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में चिंता का माहौल है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मंदिर परिसर और आसपास की पहाड़ी का तत्काल निरीक्षण कराने तथा सुरक्षा के आवश्यक इंतजाम करने की मांग की है। इससे पहले अभी हाल में चमोली जिले में बीते गुरुवार को निर्माणाधीन पनबिजली सुरंग के अंदर ज़बरदस्त भूस्खलन के कारण अचानक पानी और मलबा घुस गया। इससे आठ मजदूरों की मौत हो गई थी। सेना, NDRF (K9 यूनिट के साथ), SDRF, CISF, ITBP और स्थानीय पुलिस

के 200 से ज़्यादा जवानों ने राहत और बचाव कार्य चलाया। बचाव दल ने कई मजदूरों को बचाया भी था। जानकारी के मुताबिक, सुरंग हादसे में दो लापता श्रमिकों की तलाश के लिए बचाव एवं राहत अभियान मंगलवार को भी जारी है। एसडीआरएफ ने बताया कि सुरंग के भीतर काफी दलदल होने के बावजूद तलाश अभियान जारी है और प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच सभी टीम आपसी समन्वय से अभियान को आगे बढ़ा रही हैं। उसने बताया कि सुरंग से पानी को लगातार बाहर निकाला जा रहा है और सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए उपलब्ध संसाधनों एवं उपकरणों के माध्यम से सभी संभावित स्थानों पर गहनता से खोजबीन की जा रही है।

## इमरान खान को उनकी बिगड़ती सेहत को देखते हुए एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित

पाकिस्तान की शीर्ष अदालत ने आदेश दिया है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को उनकी बिगड़ती सेहत को देखते हुए एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने खान को 48 घंटे के भीतर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल जाने और 16 सितंबर तक वहीं रहने का निर्देश दिया है। 73 साल के पूर्व क्रिकेटर और अब राजनेता बन चुके इमरान खान 2023 से पाकिस्तान की अदियाला जेल में बंद हैं और उन पर कई मामले चल रहे हैं। उनकी पार्टी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने बार-बार आरोप लगाया है कि अधिकारियों ने उन्हें परिवार के सदस्यों और पार्टी के साथियों से मिलने से रोका है और उनकी स्वास्थ्य समस्याओं जिसमें आंखों की एक बीमारी भी शामिल है। ख़ैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी, जिनके प्रांत में खान की पार्टी की सरकार है, ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री की सेहत के मामले को उतनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए जितनी ज़रूरी है। अफरीदी ने कहा, हम न तो इमरान खान की सेहत का राजनीतिकरण करते हैं और न ही इमरान खान ने कभी किसी तरह की राहत पाने के लिए अपनी सेहत का मुद्दा उठाया है। उन्होंने मांग की कि खान का इलाज उनके निजी डॉक्टरों की देखरेख और परिवार की मौजूदगी में हो। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को इस मांग को मानने के लिए ज़रूरी नैतिक हिम्मत दिखानी चाहिए। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए अफरीदी ने चेतावनी दी कि खान की लगातार जेल में रहने से जनता में बढ़ रही निराशा उस हद तक पहुँच सकती है जहाँ शांति बहाल करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री की सुलह की अपील भी काफ़ी न हो।

## 16 भारतीय क्रू सदस्यों ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने से मना कर दिया

मार्शल आइलैंड्स के ध्वज वाले जहाज 'एएम पायनियर' (AM Pioneer) पर सवार 16 भारतीय नाविकों ने सुरक्षा जोखिमों के चलते अत्यधिक संवेदनशील 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' (Strait of Hormuz) से गुजरने से इनकार कर दिया है। क्रू सदस्यों ने भारत सरकार को आपात संदेश भेजकर मदद की गुहार लगाई है। जहाज के मास्टर (कैप्टन) अनिल राज ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि कंपनी उन्हें जान जोखिम में डालकर इस खतरनाक मार्ग से जहाज ले जाने के लिए मजबूर कर रही है। यह जहाज वर्तमान में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के रास अल खैमाह बंदरगाह पर है। 'फॉरवर्ड सीमेंस यूनियन ऑफ इंडिया' (FSUI) ने क्रू का समर्थन किया है और केंद्र सरकार से तुरंत हस्तक्षेप करने तथा नाविकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने की मांग की है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव तथा फारस की खाड़ी क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हमलों के कारण यह समुद्री मार्ग बेहद खतरनाक और जोखिमभरा हो गया है। इस मार्ग पर पहले भी भारतीय नाविकों की जान जा चुकी है। फारस की खाड़ी

क्षेत्र में लगातार हमलों के कारण बढ़ते खतरों को देखते हुए भारत के पोत परिवहन महानिदेशालय (Directorate General of Shipping) ने पहले ही सख्त आदेश जारी कर शिपिंग कंपनियों और एजेंटों को अगले आदेश तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर किसी भी भारतीय नाविक को तैनात नहीं करने के निर्देश जारी किए हैं। जहाजों की निगरानी करने वाली वेबसाइट Equasis के अनुसार, AM Pioneer का प्रबंधन मुंबई की कंपनी Alphard Maritime Private Limited करती है। यह एक ऑफशोर सप्लाई वेसल है, जो ऑफशोर तेल और गैस प्लेटफॉर्म तक उपकरण, क्रू और जरूरी सामान का परिवहन करती है। X पर अपनी पोस्ट में FSUI ने कहा कि AM Pioneer के जहाज मालिक और मैनेजर मास्टर पर 16 भारतीय क्रू सदस्यों को बहुत ज्यादा जोखिम वाले होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरने के लिए मजबूर करने का दबाव डाल रहे हैं। एसोसिएशन ने कहा, "क्रू ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। वे कम्युनिकेशन बंद करके अंधेरे में जहाज चलाकर अपनी जान जोखिम में नहीं डालेंगे।"

## संपादक की कलम से

राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' को लेकर देश में एक बार फिर बहस तेज हो गई है। सरकारी कार्यक्रमों में इसे पूरा गाने की अनिवार्यता और इससे जुड़े कानूनी प्रावधानों ने राष्ट्रवाद, सम्मान और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन का सवाल खड़ा कर दिया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इसी संदर्भ में इसकी व्यावहारिकता पर सवाल उठाते हुए कहा है कि देशभक्ति और राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान को लेकर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए, लेकिन नियम बनाते समय व्यवहारिक पहलुओं को भी ध्यान में रखना जरूरी है।'वंदे मातरम' भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रीय चेतना से गहराई से जुड़ा हुआ गीत है। इसके प्रति सम्मान देश की ऐतिहासिक विरासत का सम्मान है। लेकिन किसी राष्ट्रीय प्रतीक के प्रति सम्मान केवल इसलिए पैदा नहीं किया जा सकता कि उसके लिए कानून बना दिया गया है। सम्मान की भावना स्वाभाविक होनी चाहिए और उसे समाज में शिक्षा, जागरूकता और संवेदनशीलता के माध्यम से मजबूत किया जाना चाहिए।थरूर ने कार्यक्रमों की अवधि को लेकर जो सवाल उठाया है, वह भी विचारणीय है। यदि किसी सरकारी कार्यक्रम में राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राज्यगीत समेत कई औपचारिक प्रस्तुतियों को अनिवार्य किया जाता है, तो कार्यक्रम की अवधि बढ़ना स्वाभाविक है। सवाल यह नहीं है कि देशभक्ति के गीत कितने लंबे हैं, बल्कि सवाल यह है कि क्या हर सरकारी कार्यक्रम में एक ही तरह की अनिवार्यता जरूरी है?राष्ट्रीय सम्मान से जुड़े कानूनों का उद्देश्य लोगों में सम्मान की भावना को मजबूत करना होना चाहिए, न कि अनजाने में भय का माहौल पैदा करना। यदि किसी व्यक्ति को यह डर रहे कि किसी प्रोटोकॉल का पालन न करने पर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, तो सम्मान की भावना कहीं पीछे छूट सकती है। कानून की भूमिका अनुशासन बनाए रखने तक सीमित होनी चाहिए, जबकि राष्ट्रीय भावनाओं को मजबूत करने का काम समाज और संस्थाओं को करना चाहिए।वहीं दूसरी ओर, विपक्ष को भी ऐसे मुद्दों पर केवल राजनीतिक विरोध तक सीमित नहीं रहना चाहिए। 'वंदे मातरम' और 'जन गण मन' दोनों ही देश की राष्ट्रीय चेतना के महत्वपूर्ण प्रतीक हैं। इनका सम्मान किसी एक राजनीतिक दल की विचारधारा नहीं, बल्कि पूरे देश की साझा जिम्मेदारी है।जरूरत इस बात की है कि राष्ट्रवाद को राजनीतिक बहस का हथियार बनाने के बजाय उसे नागरिक जिम्मेदारी और संवैधानिक मूल्यों से जोड़ा जाए। राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी यह समझना भी है कि सम्मान आदेश से नहीं, विश्वास और भावना से पैदा होता है। सरकार को कानून लागू करते समय इसी संतुलन का ध्यान रखना चाहिए, ताकि 'वंदे मातरम' के सम्मान का उद्देश्य पूरा हो और यह मुद्दा राजनीतिक टकराव का कारण न बने।

# 2027 चुनावों के लिए बीजेपी ने कसी कमर

**उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात में 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने संगठनात्मक तैयारियां तेज कर दी हैं।राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने तीनों राज्यों के लिए नए प्रभारियों की नियुक्ति कर चुनावी रणनीति को धार देने का संकेत दिया है।यूपी में विनोद तावड़े, गुजरात में तरूण चुग और पंजाब में सतीश पूनिया को जिम्मेदारी देकर पार्टी ने संगठन मजबूत करने पर फोकस बढ़ाया है।**

अगले साल 2027 में उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात में विधानसभा चुनाव होने है। जहां यूपी और गुजरात में बीजेपी के सामने अपनी सत्ता बरकरार रखने, जबकि पंजाब में सत्ता बनाने की चुनौती होगी। तीनों राज्यों के चुनाव को देखते हुए पार्टी ने तैयारी भी तेज कर दी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने तीनों राज्यों के लिए प्रभारी की मंगलवार को घोषणा की है। विनोद तावड़े को यूपी, तरूण चुग को गुजरात और सतीश पूनिया को पंजाब का प्रभारी बनाया गया है। बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पिछले कुछ महीनों से चुनावी राज्यों का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान नवीन संगठन की तैयारियों की समीक्षा भी कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश और पंजाब पर पार्टी नेतृत्व का खास फोकस रहा है। संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं में सक्रियता बढ़ाने और स्थानीय राजनीतिक समीकरणों को समझने के लिए लगातार बैठकें की जा रही हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। दरअसल, चुनावी राज्यों में से बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण यूपी है। पार्टी भले ही अभी भी राज्य की राजनीति में मजबूत स्थिति में हो, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उसे कई क्षेत्रों और सामाजिक समूहों के बीच नुकसान उठाना पड़ा था। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का लक्ष्य इन कमजोरियों को दूर कर अपनी स्थिति मजबूत करना है। विनोद तावड़े बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री है और पार्टी के भरोसेमंद संगठनकर्ताओं में गिना जाते है। वे हरियाणा और बिहार के भी प्रभारी रह चुके हैं। इसके अलावा हाल के वर्षों में उनका उत्तर प्रदेश की बीजेपी गतिविधियों में भी सक्रिय दखल रहा है। विनोद तावड़े की खासियत एक बड़े जननेता के बजाय पर्दे के पीछे रहकर संगठन और राजनीतिक समीकरणों को साधने वाले रणनीतिकार की है। उनके सामने चुनौती सिर्फ विपक्ष को हराने की नहीं होगी, बल्कि सहयोगी दलों के साथ तालमेल, जातीय प्रतिनिधित्व, टिकट वितरण और बूथ स्तर तक पार्टी के संगठन को सक्रिय रखने की भी होगी। नितिन नवीन ने सतीश पूनिया को पंजाब की जिम्मेदारी दी है। दरअसल, पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी ने अपने दम पर अकेले कभी सरकार नहीं बनाई है। बीजेपी ने शिरोमणि अकाली दल के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। यहां पर पार्टी को अपना आधार विस्तार देने की जरूरत है। दरअसल, पार्टी अब राज्य में अपने दम पर संगठन और जनाधार मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इसी रणनीति के तहत सतीश पूनिया को पंजाब की जिम्मेदारी दी गई है। राजस्थान बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व नेता प्रतिपक्ष पूनिया को मजबूत संगठनकर्ता के तौर पर जाना जाता है। हरियाणा में बीजेपी के लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने के दौरान उनकी संगठनात्मक भूमिका को भी महत्वपूर्ण माना गया था। पूनिया पहले से ही पंजाब बीजेपी के संगठन को मजबूत करने की कवायद में शामिल रहे हैं। ऐसे में उनकी नियुक्ति को नई शुरुआत के बजाय पहले से चल रहे संगठनात्मक प्रयासों को आगे बढ़ाने के तौर पर देखा जा रहा है।

## CJP का दिल्ली सरकार पर हमला छात्रों की FIR वापस लेने की मांग तेज

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने मंगलवार को दिल्ली सरकार से सवाल किया कि वह उन FIRs की लिस्ट कोर्ट में क्यों नहीं सौंप रही है जिन्हें रद्द किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि छात्रों के लिए सबसे बड़ी चिंता विरोध-प्रदर्शनों के दौरान उनके खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेना है। दास ने कहा कि सरकार को मामले में देरी करने के बजाय कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए और जरूरी जानकारी सौंपनी चाहिए। ANI से बात करते हुए दास ने कहा कि जब कोर्ट (सरकार से) उन FIRs की लिस्ट मांग रहा है जिन्हें रद्द किया जाना है, तो आप उसे कोर्ट में क्यों नहीं सौंप रहे हैं? लेकिन आप (सरकार) कोर्ट में इस मामले में हिचकिचाहट दिखा रहे हैं। हमारे साथ देरी करने वाली चालें न चलें। हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने लगभग 2,800 कुख्यात अपराधियों की पहचान की है; अगर उन्हें उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है, तो वह बिल्कुल अलग मामला है। छात्रों से जुड़ा मुद्दा उनके खिलाफ दर्ज FIRs को रद्द करने का है। ये टिप्पणियाँ ऐसे समय में आई हैं जब CJP लगातार यह मांग कर रही है कि आंदोलन के दौरान छात्रों और दूसरे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज FIR को सिर्फ़ 'बंद मामले' मानने के बजाय औपचारिक रूप से वापस लिया जाए। पार्टी का कहना है कि जिन छात्रों ने विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया, उन पर सिर्फ़ आंदोलन में शामिल होने की वजह से आगे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। यह मामला 20 जुलाई को संसद तक निकाले गए उस मार्च से जुड़ा है, जिसे CJP ने जंतर-मंतर पर हफ़्तों तक चले विरोध प्रदर्शनों और भूख हड़ताल के बाद आयोजित किया था। इस मार्च में हज़ारों छात्रों ने हिस्सा लिया था। वे परीक्षा के पेपर लीक होने के मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े और परीक्षा प्रणाली में बड़े सुधारों की मांग कर रहे थे। जब प्रदर्शनकारी संसद की ओर मार्च करते हुए मध्य दिल्ली में पुलिस बैरिकेड्स पार करने की कोशिश कर रहे थे, तो सुरक्षाकर्मियों ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए जिनमें कथित तौर पर पुलिस प्रदर्शनकारियों के साथ धक्का-मुक्की करती दिखी। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने अपनी कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि बल का इस्तेमाल तभी किया गया जब कुछ प्रदर्शनकारी कथित तौर पर हिंसक हो गए और उन्होंने पत्थरबाजी की।

# नितिन नवीन को इस्तीफा सौंपने के बाद शहजाद पूनावाला ने बताया कारण

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सोमवार को BJP अध्यक्ष नितिन नवीन को अपना इस्तीफा सौंपते हुए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता समेत सभी पदों से हटने का ऐलान किया। पूनावाला ने कहा कि यह फैसला उन्होंने लंबे विचार-विमर्श के बाद लिया है। हालांकि, उन्होंने साफ किया कि उनका इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या BJP की विचारधारा से दूरी नहीं है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी छोड़ने का कारण भी बताया। एक मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में पूनावाला ने कहा कि वह करीब दो साल से पार्टी छोड़ने पर विचार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2024 से ही वह दोबारा नौकरी करने और अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने की योजना बना रहे थे। उन्होंने कहा कि राजनीति में उन्होंने 24 घंटे, सातों दिन और पूरे साल काम किया। जब उनके सामने नौकरी और राजनीति में से किसी एक को चुनने की स्थिति आई, तो उन्होंने नौकरी पर लौटने का फैसला किया। पूनावाला ने कहा कि उन्होंने पहली बार 30 जुलाई को इस्तीफा देने की पेशकश की थी, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने उन्हें अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा था। इसके बाद उन्होंने काफी सोच-विचार किया, लेकिन अंततः इस्तीफे के फैसले पर कायम रहने का निर्णय लिया। पूनावाला ने बताया कि उनके इस्तीफे के पीछे मुख्य वजह आर्थिक और निजी परिस्थितियां हैं। उन्होंने कहा कि अब वह निजी क्षेत्र में नौकरी करने जा रहे हैं और अपने वित्तीय हालात को संभालना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं संगठन से अलग हो रहा हूं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के लोगों और विचारधारा से नहीं। शहजाद पूनावाला ने BJP के सोशल मीडिया विभाग की जिम्मेदारी संभालने की अटकलों को भी खारिज किया। अमित मालवीय को हटाए जाने के बाद पार्टी ने दीपक म्हास्के को सोशल मीडिया संयोजक नियुक्त किया है। उनके साथ प्रीति गांधी, शिवानंद द्विवेदी, आलोक भट्ट और अरूण यादव को सह-संयोजक बनाया गया है। जब पूनावाला से पूछा गया कि क्या वह इस पद के लिए इच्छुक थे, तो उन्होंने साफ कहा कि उन्हें इसमें कोई रुचि नहीं थी। उनके मुताबिक, सोशल मीडिया की जिम्मेदारी बाहर से जितनी आकर्षक दिखती है, वास्तव में उतनी ही कठिन है। इस्तीफा देने से एक दिन पहले पूनावाला ने इंस्टाग्राम पर 'द मैनिफेस्टो' नाम से एक नई पहल शुरू की थी। इसमें उन्होंने खास तौर पर मध्यम वर्ग से जुड़े मुद्दे उठाए। उन्होंने सवाल किया कि भारत में टैक्स देने वाले लोगों को क्या उन देशों के बराबर सुविधाएं और बुनियादी ढांचा मिलता है, जहां

टैक्स की दरें समान हैं। उन्होंने सड़कों, स्कूलों, बुनियादी ढांचे, पेपर लीक, भ्रष्टाचार और जवाबदेही जैसे मुद्दों पर सवाल उठाए। शहजाद पूनावाला ने आर्थिक और निजी परिस्थितियों का हवाला देते हुए बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि प्रवक्ता का पद स्वैच्छिक है और सैलरी नहीं मिलती।

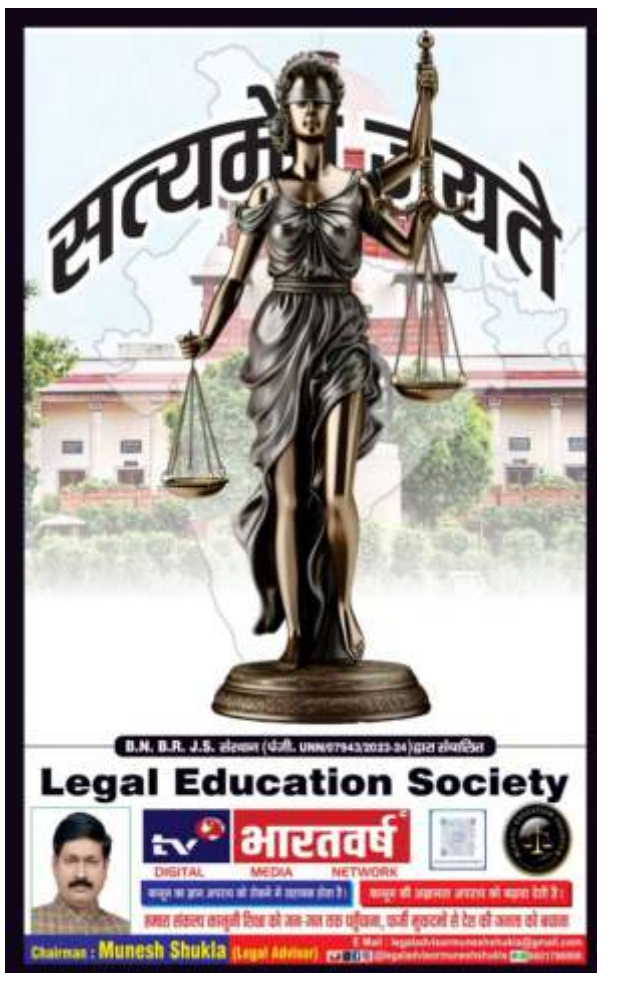

# दिल्ली में मेडिकल सीटों का बड़ा इजाफा MBBS-PG-DNB की 408 नई सीटों का प्रस्ताव

मेडिकल एडमिशन के लिए नीट काउंसलिंग 2026 चल रही है। इस बीच छात्रों के लिए खुशखबरी है। दिल्ली के मेडिकल कॉलेजों में MBBS, PG और DNB सीटों की संख्या में काफी बढ़ोतरी होने वाली है, क्योंकि दिल्ली सरकार मेडिकल एजुकेशन की क्षमता बढ़ाने के लिए एक रोडमैप तैयार कर रही है। इस योजना के तहत नए और मौजूदा मेडिकल संस्थानों में 300 MBBS सीटें और 103 PG-DNB सीटें जोड़ी जाएंगी। इसके अलावा 5 फेलोशिप सीटों का भी प्रस्ताव है, जिससे नई मेडिकल सीटों की कुल संख्या 408 हो जाएगी। इस पहल का उद्देश्य दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और स्पेशलिस्ट की कमी को दूर करना है। यहां जाने कि कहां कितनी सीटें बढ़ेंगी। सीटें बढ़ने से दिल्ली के सरकारी संस्थानों में मेडिकल एडमिशन और पढ़ाई की क्षमता बढ़ेगी और भविष्य में बड़ी संख्या में डॉक्टर और विशेषज्ञ तैयार होंगे। ग्रीनफील्ड प्लान के तहत द्वारका में इंदिरा गांधी अस्पताल (IGH) और गुरु गोबिंद सिंह अस्पताल में बन रहे मेडिकल कॉलेजों में से हर 1 में 150 MBBS सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव है। इन दोनों संस्थानों में कुल मिलाकर 300 नई अंडरग्रेजुएट सीटें बढ़ाई जाएंगी। डॉ. बीएसए मेडिकल कॉलेज में MBBS सीटों की संख्या 125 से बढ़ाकर 200 करने का प्रस्ताव है। मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज (MAIDS) में BDS सीटों की संख्या भी 50 से बढ़ाकर 70 करने का प्रस्ताव है। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज (MAMC) में PG सीटों की संख्या 260 से बढ़ाकर 295 करने का प्रस्ताव है।

MAIDS में PG सीटें 22 से बढ़कर 42 हो जाएंगी।

BSA मेडिकल कॉलेज में भी 24 सीटों वाले नए PG कोर्स शुरू होने की उम्मीद है। सरकार की योजना के तहत अलग-अलग सरकारी मेडिकल संस्थानों में 103 नई PG/DNB सीटें जोड़ी जाएंगी, जिनमें 67 MD/MS और 36 DNB सीटें शामिल हैं। इसके अलावा 5 फेलोशिप सीटों का भी प्रस्ताव है। तीन GTB हॉस्पिटल में और 2 दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में। इससे PG और DNB और फेलोशिप लेवल पर नई सीटों की कुल संख्या 108 हो जाएगी। सरकार DM, MCh और स्ट्रक्चर्ड पोस्ट-डॉक्टरल फेलोशिप जैसे सुपर-स्पेशियलिटी प्रोग्राम को बढ़ाने पर भी काम कर रही है। नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) और दूसरे संबंधित अधिकारियों से जरूरी मंजूरी लेने की प्रक्रिया अभी चल रही है। नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने 2026-27 सेशन के लिए MBBS की सीटों का मैट्रिक्स जारी किया था। मौजूदा सेशन में MBBS की 9,911 सीटें बढ़ाई गई हैं और इस तरह से सीटों की संख्या 1,27,028 से बढ़कर 1,36,939 हो गई है। भारत में 823 मेडिकल कॉलेजों में कुल 136,939 MBBS सीटें हैं। इनमें से 441 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 63,296 सीटें उपलब्ध हैं। 382 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में 73,643 सीटें हैं।

## आईबीपीएस पीओ प्रारंभिक परीक्षा 22-23 अगस्त को आयोजित होगी।

आईबीपीएस पीओ प्रारंभिक परीक्षा 22 और 23 अगस्त, 2026 को प्रस्तावित है। परीक्षा में अब महज चार दिन शेष हैं। ऐसे में नई चीजें पढ़ने के बजाय अब तक की तैयारी को मजबूत करना ज्यादा जरूरी है। अभ्यर्थियों को रिवीजन, मॉक टेस्ट, समय-प्रबंधन और मानसिक संतुलन पर ध्यान देना चाहिए। अंतिम दिनों में सही रणनीति और आत्मविश्वास बेहतर प्रदर्शन की कुंजी बन सकते हैं। पिछले वर्षों की कटऑफ और न्यूनतम क्वालिफाइंग स्कोर से परीक्षा के स्तर का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन अंतिम चार दिनों में बार-बार कटऑफ देखना फायदेमंद नहीं होगा। हर वर्ष प्रश्नों की कठिनाई, अभ्यर्थियों के प्रदर्शन और रिक्तियों के आधार पर कटऑफ बदल सकती है। इसलिए किसी एक आंकड़े को लक्ष्य बनाने के बजाय अपनी सटीकता और प्रयासों की संख्या पर ध्यान दें। यदि मॉक टेस्ट में लगातार अच्छा स्कोर आ रहा है, तो परीक्षा में भी उसी स्तर के प्रदर्शन को दोहराने की कोशिश करें। ज्यादा प्रश्न हल करने के चक्कर में गलतियां करने से बेहतर है कि समझकर सही प्रश्नों का चयन करें और उन्हें सटीकता के साथ हल करें। अंतिम दिनों में नई ट्रिक, शॉर्टकट या रणनीति अपनाने से बचें। मॉक टेस्ट में जिस तरीके से आपकी गति और सटीकता बेहतर रही है, परीक्षा में भी उसी रणनीति को अपनाएं। कठिन पजल, लंबे डाटा इंटरप्रिटेशन या ज्यादा समय लेने वाले प्रश्नों को बाद के लिए छोड़ दें। हर प्रश्न हल करना जरूरी नहीं है। समय का सही इस्तेमाल और प्रश्नों का चयन ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए उन्हीं प्रश्नों को हल करें, जिन्हें आप आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं।

## उन्नति हुड्डा ने अपने पहले BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप अभियान की शुरुआत जीत के साथ की

## ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में 100 सिक्स लगाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज बन गए

ऋषभ पंत ने इतिहास रच दिया है, जो काम टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम का कोई बल्लेबाज नहीं कर सका, वो काम पंत ने कर दिखाया है। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट के चौथे दिन जैसे ही दूसरा सिक्स लगाया, उनके सिक्स की संख्या 100 तक जा पहुंची। उन्होंने एडम गिलक्रिस्ट की बराबरी कर ली है, अब केवल दो ही बल्लेबाज उनसे आगे बचे हैं। हालांकि बॉल और मैच के हिसाब से देखें तो यहां तक पहुंचने वाले वे दुनिया के सबसे तेज बल्लेबाज हैं। इसलिए ये एक विश्व कीर्तिमान भी है। भारत बनाम श्रीलंका गॉल टेस्ट के चौथे दिन टीम इंडिया की दूसरी पारी में ऋषभ पंत ने जबरदस्त बल्लेबाजी का मुजायरा पेश किया। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए चौके और छक्के लगाए। इस दौरान जैसे ही उन्होंने अपना दूसरा सिक्स लगाया, उनके टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के पूरे हो गए। एडम गिलक्रिस्ट ने भी 100 छक्के लगाए हैं। पंत उनकी बराबरी पर पहुंच गए हैं। टेस्ट में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने का विश्व कीर्तिमान इंग्लैंड के बेन स्टोक्स के नाम है, उन्होंने 138 छक्के लगाए हैं। दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैक्कुलम हैं, जिन्होंने 107 सिक्स लगाए हैं। पंत ने इसी 100वें छक्के के साथ अपना अर्धशतक भी पूरा किया। वे इस वक्त अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। खास बात ये है कि इस टेस्ट में भारत की लीड अब 300 से अधिक रन की हो गई है। अब ऐसा लगता है कि टीम इंडिया इस मैच को हारेगी तो नहीं, क्योंकि आखिरी पारी में इतने रन बनाना आसान काम नहीं होता। हां, अगर श्रीलंका ने अच्छा खेल दिखाया तो मैच ड्रॉ हो सकता है। वैसे कोशिश तो यही होगी कि ये इस मैच को अपने नाम किया जाए।

## 2025 के भारत के नेशनल स्पोर्ट्स अवॉर्ड का ऐलान अलग-अलग खेलों के 17 खिलाड़ियों को अर्जुन अवॉर्ड

: भारत में हर साल खिलाड़ियों के नेशनल स्पोर्ट्स अवॉर्ड दिए जाते हैं। खेल मंत्रालय ने 2025 के नेशनल स्पोर्ट्स अवॉर्ड का ऐलान कर दिया है। इस बार किसी भी खिलाड़ी को खेल रत्न अवॉर्ड नहीं दिया गया है। वहीं 17 खिलाड़ियों को अर्जुन अवॉर्ड के लिए चुना गया है। वहीं, 3 कोचों को द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। भारत के उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर, सरकार ने अलग-अलग श्रेणी में खिलाड़ियों, कोच और संस्थाओं को अवॉर्ड देने का फैसला किया है।अर्जुन पुरस्कार' खेल के क्षेत्र में पिछले चार वर्षों में अच्छे प्रदर्शन और नेतृत्व, खेल-भावना और अनुशासन की भावना दिखाने वाले एथलीटों को दिया जाता है। शानदार प्रदर्शन के लिए अर्जुन अवॉर्ड पाने वाले प्रमुख नामों में हाई जम्पर और डेकाथलॉन के एथलीट तेजस्विन शंकर, स्प्रिंटर मुहम्मद अजमल वी और प्रियंका गोस्वामी, बैडमिंटन खिलाड़ी ट्रेसा जॉली और गायत्री गोपीचंद, शतरंज खिलाड़ी विदित गुजराती और दिव्या देशमुख, हॉकी खिलाड़ी लालरेम्सियामी और राजकुमार पाल और शूटर अखिल श्योराण शामिल थे। अर्जुन पुरस्कार (लाइफटाइम) फुटबॉलर आई अरुमनायगम को दिया गया है। यह पुरस्कार उन खिलाड़ियों को सम्मान देने और प्रेरित करने के लिए दिया जाता है जिन्होंने खेल के क्षेत्र में योगदान दिया है और खेल से संन्यास के बाद किसी न किसी रूप में जुड़कर उसे बढ़ावा देने में योगदान देते रहते हैं।

## भारत ने श्रीलंका के सामने 372 रनों का लक्ष्य रखा

भारत ने गॉल में खेले जा रहे पहले टेस्ट की पहली पारी में 462 रन बनाए। इसके जवाब में श्रीलंका की टीम ने अपनी पहली पारी में 284 रन बनाए। पहली पारी के आधार पर भारत को 178 रनों की बढ़त हासिल हुई, लेकिन टीम इंडिया अपनी दूसरी पारी में महज 193 रनों पर सिमट गई। इस तरह भारतीय टीम ने मेजबानों के सामने 372 रनों का लक्ष्य रखा है। अभी इस मैच में करीब चार सेशन का खेल बाकी है। अब सवाल ये है कि क्या श्रीलंकाई टीम इस टोटल को चेज कर सकती है। आइये इससे पहले गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में चौथी पारी के सबसे बड़े रनचेज पर नजर डालते हैं।गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में टेस्ट मुकाबले 1998 से खेले जा रहे हैं। इस मैदान पर अब तक चौथी पारी में मात्र एक बार ही 300+ स्कोर चेज हो सका है। जब 2022 में मेजबान श्रीलंका ने पाकिस्तान टीम के सामने 342 रनों का लक्ष्य रखा था। उस मुकाबले में बाबर आजम की अगुवाई वाली टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर सफल रन चेज किया था। उस

मुकाबले में अब्दुल्ला शफीक ने पाकिस्तान की ओर से नाबाद 160 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली थी। वहीं, मेजबान श्रीलंका की बात करें तो गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में सिर्फ एक बार ही चौथी पारी में 200+ रनों का लक्ष्य सफलतापूर्वक चेज किया है। वह मुकाबला मेजबान टीम ने 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। उस मैच में कीवी टीम ने श्रीलंका के सामने 268 रनों का टारगेट रखा था। दिमुथ करुणारत्ने की 122 रनों की शानदार शतकीय पारी के दम पर श्रीलंका ने उस मैच में 6 विकेट से जीत दर्ज की थी। बता दें कि मेजबान श्रीलंकाई टीम गॉल में अब तक 13 बार ही रन चेज करने उतरी है, जिसमें से उसने 6 मैच जीते हैं, तो 6 ही हारे हैं, जबकि एक मैच ड्रॉ रहा है। भारत ने गॉल में श्रीलंका को 2008 में जीत के लिए चौथी पारी में 307 रनों का टारगेट दिया था। लेकिन, मेजबान टीम सिर्फ 136 रनों पर ही ढेर हो गई थी। उसके बाद 2017 में भारत के 550 रनों के विशाल लक्ष्य के सामने श्रीलंकाई टीम महज 245 रनों पर सिमट गई थी।

मोहब्बत की मिसाल

# भारतीय कपल को विदा करते वक्त रो पड़ी अमेरिकी महिला

अमेरिका एक ऐसा देश है, जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने में पूरी दुनिया के लोगों की मेहनत लगी है. यह प्रवासियों की मेहनत और कुर्बानी से बना है. अमेरिका में लाखों भारतीय रहते हैं, वहां मेहनत करते हैं और अब वहीं रच-बस गए हैं. लेकिन दूसरी हकीकत यह भी है कि अमेरिका में बाहरी बनाम मूल निवासी की राजनीति को लेकर बहस होती रही है. ट्रंप के दोबारा सत्ता में आने में इस राजनीति का काफी हद तक योगदान माना जाता है. वहां काम करने वाले भारतीयों के खिलाफ ट्रंप के समर्थकों की ओर से नफरत फैलाने के आरोप भी लगते रहे हैं. लेकिन भारतीय जहां भी जाते हैं, अपने साथ मोहब्बत ले

जाते हैं और कई बार नफरत को भी पीछे छोड़ देते हैं.
सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है. अमेरिका से भारत लौट रहे एक भारतीय कपल की उनके अमेरिकी पड़ोसी के साथ हुई भावुक विदाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

राजस्थानी रंग में दिखा मॉडर्न हुनर

# तीज की सवारी में छाई 9 साल की सिनाया

विशाल शर्मा, आजतक

जयपुर की तीज सवारी में इस बार रंग-बिरंगे राजस्थानी परिधानों और लोक कलाकारों के बीच एक नन्ही कलाकार ने खास ध्यान खींचा. महज 9 साल की सिनाया बियानी ने अपनी कला और संतुलन से ऐसी प्रस्तुति दी कि वहां मौजूद लोग उन्हें देखते रह गए. सिनाया को प्यार से 'जयपुर हूपर' भी कहा जाता है. राजस्थानी वेशभूषा में सजी सिनाया ने हूला-हूप के साथ अपनी कला का प्रदर्शन किया. उनकी प्रस्तुति में राजस्थान की पारंपरिक छवि और आधुनिक प्रदर्शन कला का खूबसूरत मेल नजर आया.हूला-हूप एक गोल छल्ला होता है, जिसे कमर, हाथ या शरीर के दूसरे हिस्सों के आसपास घुमाया जाता है. इसमें

शरीर का संतुलन और तालमेल बनाए रखना पड़ता है. तीज सवारी के रंगीन माहौल के बीच उनका अंदाज लोगों को खासा पसंद आया.
सिनाया ने बेहद कम उम्र में हूला-हूप की कला में अपनी अलग पहचान बनाई है. वह अलग-अलग मंचों पर अपनी प्रस्तुतियां दे चुकी हैं और हूला-हूप के जरिए लगातार नए करतब दिखाती रही हैं. जयपुर की तीज सवारी में भी उन्होंने इसी हुनर को राजस्थानी अंदाज के साथ पेश किया. पारंपरिक पोशाक में हूला-हूप के साथ उनका संतुलन और प्रदर्शन देखने लायक था.

### 'जयपुर हूपर' के नाम से बनी पहचान

सिनाया को उनकी इसी प्रतिभा के चलते 'जयपुर हूपर' के नाम से जाना जाता है. इतनी कम उम्र में हूला-हूप में उनकी पकड़ ने उन्हें अलग पहचान दिलाई है.उनकी कहानी की खास बात यह है कि वह पारंपरिक भारतीय परिधान और राजस्थान की संस्कृति को अपनी आधुनिक कला के साथ जोड़कर प्रस्तुत करती हैं.

5 महीने से था बेरोजगार

# AI की मदद से मिली 1.5 करोड़ की जॉब

आज के समय में नौकरी पाना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है. अच्छी डिग्री और सालों का अनुभव होने के बावजूद कई लोगों को लगातार इंटरव्यू देने पड़ते हैं और अच्छी नौकरी नहीं मिलती. ऐसे ही एक शख्स की कहानी इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है.
इस शख्स ने बताया कि नौकरी जाने के बाद उसने करीब पांच महीने तक नई नौकरी खोजी, लेकिन बार-बार निराशा ही हाथ लगी. आखिर में उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली और उसकी यही रणनीति काम कर गई. अब उसे करीब ₹1.5 करोड़ सालाना पैकेज वाली नई नौकरी

मिल गई है. इस शख्स ने अपनी कहानी रेडिट पर शेयर की. उसने बताया कि वह लगभग 10 साल तक एक ही कंपनी में काम करता रहा था. इस दौरान उसे तीन बार प्रमोशन भी मिला. लेकिन फरवरी के आखिर में अचानक कंपनी ने उसे नौकरी से निकाल दिया. यह फैसला उसके लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था.

जन्म लेते ही बच्चों पर हो जाता है मालिक का हक

# गुलामों के द्वीप की अनूठी कहानी

दुनिया 21वीं सदी में पहुंच चुकी है. गुलामी को खत्म हुए भी कई देशों में 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं. लेकिन इंडोनेशिया में एक ऐसा द्वीप है, जहां आज भी कुछ लोग जन्म लेते ही किसी और की संपत्ति माने जाते हैं. उन्हें बचपन से ही मालिक की सेवा करनी पड़ती है. बिना मजदूरी के खेतों में काम करना, घर के सारे काम संभालना और मालिक के हर आदेश का पालन करना उनकी जिंदगी का हिस्सा होता है. इतना ही नहीं, कई लोगों का आरोप है कि यहां गुलाम महिलाओं के साथ यौन शोषण और मारपीट जैसी घटनाएं भी होती हैं.यह कहानी इंडोनेशिया के सुम्बा द्वीप की है, जो बाली के मशहूर समुद्री तटों से महज दो घंटे की दूरी पर है. बाहर से देखने पर

यह जगह खूबसूरत झरनों, पहाड़ियों और समुद्र के बीच बसा एक शांत पर्यटन स्थल नजर आता है, लेकिन इसके भीतर सदियों पुरानी एक ऐसी परंपरा आज भी सांस ले रही है, जिसे दुनिया गुलामी कहती है.
'मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे आजाद हों'
सुम्बा के एक गांव में रहने वाला एक व्यक्ति, जो खुद इसी व्यवस्था में पैदा हुआ, अपनी पहचान छिपाते हुए बताता है कि बचपन से ही उसे मालिक के खेतों में काम करने के लिए मजबूर किया जाता था.
वह कहता है, अगर मैं ठीक से काम नहीं करता था तो मुझे पीटा जाता था. मुझ पर पानी फेंका जाता था. स्कूल से लौटते ही खेतों में काम करना पड़ता था.

तृषा विवाद पर DMK का विजय पर हमला

# स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में पहली पंक्ति में बैठाने पर उठाए सवाल

DMK नेता उदयनिधि स्टालिन पिछले दिनों अपने एक बयान को लेकर मुश्किल में फंस गए। कावेरी विवाद प्रदर्शन के दौरान स्टॉलिन ने एक्ट्रेस तृषा कृष्णन को लेकर कुछ ऐसा कह दिया, जिसके बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया और कथित विवादित टिप्पणी के बाद स्टालिन को हिरासत में ले लिया गया। अब तृषा पर डबल मीनिंग कमेंट्स के बाद उदयनिधि स्टालिन की पार्टी के मुखपत्र ने स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान एक्ट्रेस तृषा कृष्णन की मौजूदगी और पहली पंक्ति में उनके बैठने की व्यवस्था को लेकर सीएम विजय पर निशाना साधा है। कार्यक्रम के दौरान तृषा, विजय के माता-पिता एसए चंद्रशेखर और शोभा चंद्रशेखर के साथ बैठी थीं।डीएमके के आधिकारिक मुखपत्र 'मुरासोली' में छपे एक संपादकीय में DMK ने सीएम विजय को निशाने पर लिया। डीएमके ने फोर्ट सेंट जॉर्ज में हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान तृषा कृष्णन को पहली पंक्ति में बैठाने और उनके साथ एक-दूसरे का अभिवादन करने को लेकर विजय की कड़ी आलोचना की। पार्टी ने उनके इस व्यवहार को मर्यादा के खिलाफ और शर्मनाक बताया है। डीएमके ने अपने संपादकीय में लिखा है- 'स्वतंत्रता दिवस समारोह के

दौरान मुख्यमंत्री विजय की गरिमा पूरी तरह से तार-तार हो गई। बिना किसी शर्म या झिझक के, उन्होंने एक एक्ट्रेस के बैठने की व्यवस्था पहली पंक्ति में की और बार-बार एक-दूसरे को सलामी देते रहे। ये सीन ऐसा था, जो उन्हें वोट देने वाले लोग भी नहीं पचा पाए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर ऐसा व्यक्ति सामने आया है, जो खुलेआम ऐसी अभद्रता और घिनौनी हरकत करता है और इसे सही ठहराने की सोचता है।' अब तक विजय या उनकी पार्टी टीवीके ने इस आलोचना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। बता दें, विजय लंबे समय से अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। विजय की पत्नी संगीता ने कुछ महीने पहले स्थानीय चेन्गलपट्टू फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दी थी। उन्होंने विजय पर एक अभिनेत्री के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोप लगाए थे, जिसके बारे में उन्हें 2021 में पता चला था। हालांकि, अब संगीता ने विजय से तलाक की अर्जी वापस ले ली है। लंबे समय से मीडिया और राजनीतिक गलियारों में दोनों के रिश्ते को लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन, अब जब संगीता ने तलाक की अर्जी वापस ले ली है तो विजय के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है।

# BSP पर मंडराया राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खोने का खतरा

बसपा की चुनावी स्थिति लगातार कमजोर होने के बीच पार्टी के सामने अब अपना राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बचाने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है।राज्यसभा में बसपा के एकमात्र सांसद का कार्यकाल नवंबर में खत्म होगा, जबकि यूपी विधानसभा और लोकसभा में पार्टी का कोई सदस्य नहीं है।2027 में यूपी, पंजाब और उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव बसपा के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं, जहां बेहतर प्रदर्शन राष्ट्रीय दर्जा बचाने की उसकी उम्मीद तय करेगा।

बहुजन समाज पार्टी (BSP) जल्द ही लोकसभा, राज्यसभा सहित उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद में शून्य सदस्य वाली पार्टी बन जाएगी। उसके राज्यसभा में एक मात्र सदस्य रामजी गौतम हैं, जिनका कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म हो जाएगा। यूपी विधानसभा में उसके एक मात्र विधायक उमाशंकर सिंह थे, जिनका 5 अगस्त को देहावसान हो गया। लोकसभा और उत्तर प्रदेश विधान परिषद में बसपा का कोई सदस्य नहीं है। उसके फिलहाल सिर्फ तीन विधायक बिहार, पंजाब और उत्तराखंड में हैं। चुनावों में बसपा का वोट प्रतिशत काफी नीचे गिरता जा रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग की निर्धारित शर्तें पूरी न करने पर उसका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिन सकता है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव बहुजन समाज पार्टी (BSP) के लिए अपना भविष्य तय करने की अग्निपरीक्षा है। अगले साल यूपी के अलावा पंजाब और उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव बीएसपी के लिए एक ऐसा अवसर हैं, जिनमें वह अपना राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा बचा सकती है। बीएसपी का लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है। राज्यसभा में एक सांसद है, जिसका कार्यकाल नवंबर में समाप्त होने वाला है। उत्तर प्रदेश में पार्टी का न तो कोई विधायक हैस न ही कोई एमएलसी है। उसके सिर्फ पंजाब, बिहार और उत्तराखंड में एक-एक एमएलए हैं। सभी चुनावों बीएसपी का वोट शेयर गोता लगाता गया है। इससे उसके भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं। करीब 42 साल पहले 14 अप्रैल 1984 को गठित बहुजन समाज पार्टी (बसपा) को सन 1996 में चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय दल (National Party) का दर्जा दिया था और इसे 'हाथी' चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया था। कांशीराम के बाद इस दल की बागडोर मायावती को मिली। मायावती ने उत्तर प्रदेश में अलग-अलग समय पर चार बार बीएसपी की सरकारें भी बनाईं। हालांकि अब बसपा का सितारा अस्त होता दिखने लगा है। वह राष्ट्रीय दल के लिए निर्धारित मापदंड पूरे करने में विफल हो रही है। इन हालात में उसका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिन सकता है। देश में किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा बरकरार रखने के लिए तीन में से कम से कम एक शर्त को पूरा करना होता है। यदि कोई राष्ट्रीय दल इन तीन में से कोई भी शर्त पूरी नहीं करता तो चुनाव आयोग उसका राष्ट्रीय दल का दर्जा समाप्त कर सकता है। राज्यों में मान्यता: वही पार्टी राष्ट्रीय दल बनी रह सकती है जिसे कम से कम चार अलग-अलग राज्यों में 'राज्य स्तरीय दल' (State Party) के रूप में मान्यता हासिल हो।

चुनाव में वोट और सीटें: वही पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी रह सकती है जिसने लोकसभा या विधानसभा चुनाव में चार या अधिक राज्यों में कुल वैध मतों के कम से कम 6 प्रतिशत वोट हासिल किए हों और इसके साथ उसने किसी एक या अधिक राज्यों में लोकसभा की कम से कम 4 सीटें जीती हों।

लोकसभा में सीटें : वह पार्टी जिसने लोकसभा चुनाव में कम से कम 2 प्रतिशत सीटें जीती हों, जो कि वर्तमान लोकसभा सदस्य संख्या के हिसाब से कम से कम 11 सीटें होती हैं, और जिसके सांसद कम से कम तीन अलग-अलग राज्यों से चुने गए हों, राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल कर सकती है। बीएसपी के सामने अब सबसे बड़ी समस्या पार्टी का राष्ट्रीय दल का दर्जा बचाने की है। सन 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में बीएसपी को मात्र 2.04 फीसदी वोट मिले थे और वह कोई भी सीट नहीं जीत सकी थी। उसके देश की तीन विधानसभाओं में एक-एक विधायक हैं। बिहार में रामगढ़ सीट से सतीश कुमार यादव, पंजाब में नवांशहर से डॉ नछत्तर पाल और उत्तराखंड में लक्सर विधानसभा सीट से मोहम्मद शहजाद बसपा के विधायक हैं।

## बारिश से पानी-पानी हुआ लखनऊ, बाढ़ की चपेट में यूपी के 12 जिले

राजधानी लखनऊ में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है। शहर के कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हो गईं और जगह-जगह जलभराव की स्थिति बन गई। बारिश का पानी सड़कों पर जमा होने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। कई प्रमुख मार्गों और निचले इलाकों में पानी भरने से वाहनों की रफ्तार थम गई। दोपहिया वाहन चालकों को सबसे अधिक दिक्कत हुई। जलभराव के कारण कई स्थानों पर यातायात भी प्रभावित रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से बारिश के दौरान हर बार ऐसी स्थिति बनती है। लगातार बारिश के चलते नगर निगम और संबंधित विभागों की टीमों को जल निकासी के लिए लगाया गया है। ताकि, लोगों को होने वाली परेशानियों से निजात दिलाया जा सके। इधर सोमवार को प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में कहीं मध्यम तो कहीं भारी बारिश देखने को मिली। सोनभद्र और बरेली में 140 मिमी से अधिक पानी बरसा। राजधानी लखनऊ समेत दिल्ली से सटे जिलों में भी अच्छी बारिश हुई। मौसम विभाग से मिले आंकड़ों के मुताबिक सोनभद्र में सबसे अधिक 147.2 मिमी बारिश दर्ज की गई। बरेली में 141, प्रयागराज में 126, रायबरेली में 88.4, लखीमपुर खीरी में 84 और शाहजहांपुर में 80.2 मिमी बारिश हुई। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि 17 अगस्त तक प्रदेश में कुल 398.6 मिमी बारिश हुई है, जबकि सामान्य बारिश 496.3 मिमी होनी चाहिए थी। यानी अब तक बारिश सामान्य से 20 प्रतिशत कम है।

## विनोद तावड़े आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की कमान संभालेंगे

भारतीय जनता पार्टी ने आगामी चुनावों को देखते हुए तीन राज्यों के प्रभारियों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें सबसे अहम नाम महाराष्ट्र की सियासत में गहरी पकड़ रखने वाले दिग्गज नेता विनोद तावड़े का है जिन्हें, यूपी का प्रभारी बनाया गया है। उनके साथ जगदीश ईश्वरभाई पटेल को सह-प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। विनोद तावड़े आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की कमान संभालेंगे। आपको बता दें कि यूपी प्रभारी का पद पिछले 2 सालों से खाली था। इससे पहले 2022 से विनोद तावड़े बिहार के प्रभारी थे। दरअसल बीजेपी में किसी भी प्रदेश प्रभारी की भूमिका बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण होती है। प्रभारी केंद्रीय नेतृत्व और राज्य संगठन के बीच एक मजबूत पुल यानी समन्वय का काम करते हैं। इसके अलावा उन्हें पार्टी संगठन का विस्तार करने, बड़े नेताओं और जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल बैठाने और पार्टी की चुनावी रणनीति को जमीन पर उतारने जैसी बड़ी जिम्मेदारी निभानी होती है। वे संगठनात्मक कार्यक्रमों की निगरानी करते हैं और समय-समय पर प्रदेश नेतृत्व को रिपोर्ट भी भेजते हैं। विनोद तावड़े को बीजेपी में मजबूत संगठनकर्ता के तौर पर जाना जाता है। भाजपा ने महाराष्ट्र के रहने वाले विनोद तावड़े पर अपना भरोसा जताया है। तावड़े का जन्म 20 जुलाई, 1964 को मुंबई के

गिरगांव इलाके में एक मराठी परिवार में हुआ था। उन्होंने पार्ले कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की है। वह बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े रहे हैं और बाल स्वयंसेवक के रूप में काम कर चुके हैं। उन्हें एक कुशल संगठनकर्ता के साथ-साथ एक बेहतरीन प्रशासक भी माना जाता है। विनोद तावड़े फिलहाल भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। साल 1995 में उन्हें पहली बार बीजेपी की तरफ से महाराष्ट्र का महासचिव बनाया गया था। उनकी बेहतरीन सांगठनिक क्षमता को देखते हुए पार्टी नेतृत्व ने उन्हें 2002 में फिर से यह जिम्मेदारी सौंपी। तावड़े का सियासी सफर तेजी से आगे बढ़ता गया और 1999 में उन्हें मुंबई महानगर इकाई के अध्यक्ष पद की कमान दी गई। बताया जाता है कि मुंबई अध्यक्ष पद के लिए चुने गए वह सबसे कम उम्र के नेता थे जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। विनोद तावड़े अपनी काबिलियत के दम पर राजनीति की सीढ़ियां चढ़ते गए। साल 2014 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें बोरीवली सीट से अपना प्रत्याशी बनाया। तावड़े ने इस सीट पर शानदार जीत दर्ज की और विधायक बने। इसके बाद देवेन्द्र फडणवीस की सरकार में उन्हें शिक्षा विभाग समेत उच्च और तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, मराठी भाषा और सांस्कृतिक मामलों का कैबिनेट मंत्री बनाया गया। वह 12वीं और 13वीं लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की समन्वय समिति के प्रमुख सदस्य भी रहे हैं।

## पारा में अवैध डेयरियों पर कार्रवाई के दौरान पथराव दो महिलाएं गिरफ्तार; 200 भैंसें जब्त

पारा में अवैध डेयरियों के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम पर पथराव और हमला करने के मामले में पुलिस ने दो आरोपी महिलाओं खुशबू और आफरीन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले में नामजद और अज्ञात समेत कुल 24 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। नगर निगम की कैटल कैचर टीम पर हमले के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। मंगलवार को नगर निगम की टीम के साथ 3 थानों की फोर्स और एक कंपनी पीएसी बल पहुंचा। सभी जवान हेलमेट, बुलेटप्रूफ जैकेट पहने हुए थे। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में निगम की टीम ने 4 मोहल्लों से करीब 200 भैंसें उठवा लीं। दरअसल, रविवार को नगर निगम जोन-6 की टीम पुलिस बल के साथ पारा में अवैध डेयरियों के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची थी। पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अभिनव वर्मा के मुताबिक टीम ने कार्रवाई शुरू की तो कुछ लोगों ने विरोध करते हुए पथराव कर दिया। हमलावरों ने बुद्धेश्वर चौकी प्रभारी दरोगा विनय पटेल को दौड़ाकर पीटा। आरोप है कि

उन पर लोहे की चेन से भी हमला किया गया। मारपीट में उनकी वर्दी फट गई और वह कीचड़ में गिरकर घायल हो गए। उनके सिर में छह टांके लगे हैं।हमले में नगर निगम के तीन कर्मचारी अवधेश कुमार, अभिनव और फुरकान भी घायल हुए। इसके अलावा निगम के तीन सरकारी वाहनों के शीशे तोड़ दिए गए। मामले में चौकी प्रभारी और नगर निगम की ओर से पारा थाने में तहरीर दी गई है। इंस्पेक्टर पारा सुरेश सिंह के मुताबिक अबरार, इमरान, सालून, सुबिल, सराफत, अतीक, आशिफ, वारिस, नसीम, रानू, जीशान और नाफिस समेत 12 नामजद और 12 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

### वित्तीय अनियमितताओं के खिलाफ 2020 से 2026 तक 866 अस्पतालों पर कार्रवाई

योगी सरकार द्वारा आयुष्मान कार्ड धारक मरीजों के इलाज में लापरवाही, नियमों के उल्लंघन और वित्तीय अनियमितताओं पर लगातार आयुष्मान योजना से जुड़े अस्पतालों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर वर्ष 2020 से 2026 तक कुल 866 अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इनमें सबसे अधिक 648 अस्पतालों का डी-इम्पैनलमेंट किया गया जबकि 61 अस्पतालों को योजना से निलंबित किया गया। वहीं 17 अस्पतालों में विशेषता को डी-इम्पैनलमेंट किया गया है। इसके अलावा 140 अस्पतालों पर पेनाल्टी की कार्रवाई करते हुए साढ़े आठ करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। इनसे अब तक 4 करोड़ रुपये से अधिक जुर्माने की धनराशि वसूली गई है। साचीज की सीईओ अर्चना वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आयुष्मान कार्ड धारक मरीजों के गुणवत्तापूर्ण इलाज को लेकर काफी गंभीर हैं। ऐसे में सीएम योगी की मंशा के अनुरूप मरीजों के इलाज में लापरवाही और मानकों को पूरा न करने वाले अस्पतालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाती है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026 में लापरवाही पर 318 अस्पतालों के खिलाफ एक्शन लिया गया।

## लखनऊ में MEA अधिकारी बनकर होटल में फर्जी छापा, दो गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पॉश इलाके गोमतीनगर में खुद को विदेश मंत्रालय (MEA) का अधिकारी बताकर होटल में फर्जी छापेमारी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक, 15 अगस्त की देर रात तीन संदिग्ध लोग गोमतीनगर के विकासखंड-3 स्थित होटल क्रिस्टेलिया में पहुंचे और खुद को विदेश मंत्रालय का अधिकारी बताकर होटल कर्मचारियों पर रौब जमाया। आरोप है कि संदिग्धों ने होटल का गेट अंदर से लॉक कराया, कर्मचारियों के साथ मारपीट की और कमरों में ठहरे मेहमानों से भी पूछताछ व तलाशी ली। मामले की सूचना मिलने के बाद गोमतीनगर पुलिस मौके पर पहुंची और दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नोएडा निवासी अभिनव सिंह और मेरठ निवासी शिवम चौहान के रूप में हुई है। तीसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। होटल संचालक की ओर से पुलिस को दी गई तहरीर के मुताबिक, 15 अगस्त की रात करीब एक बजे तीन संदिग्ध होटल में दाखिल हुए। उन्होंने खुद को विदेश मंत्रालय का उच्चाधिकारी बताते हुए रिसेप्शन का दरवाजा अंदर से बंद करा दिया। जब नाइट मैनेजर कुमार सर्वोत्तम पाठक ने उनसे आधिकारिक पहचान पत्र दिखाने को कहा तो आरोपियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी और जान से मारने की धमकी दी।

आरोप है कि इसके बाद मैनेजर और एक अन्य कर्मचारी के साथ मारपीट की गई और होटल के कर्मचारियों के मोबाइल फोन भी अपने कब्जे में ले लिए गए। पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक, इसके बाद आरोपी होटल की पहली और दूसरी मंजिल पर पहुंचे। उन्होंने कमरों के दरवाजे खटखटाकर वहां ठहरे मेहमानों को परेशान किया और उनकी तलाशी लेने का प्रयास किया। आरोपियों ने रिसेप्शन काउंटर पर रखे जरूरी रिकॉर्ड और दस्तावेज भी खंगाले। शिकायत के अनुसार, कुछ दस्तावेज आरोपियों ने अपने साथ लाई गई गाड़ी में रख लिए। हंगामे के बीच होटल के एक कर्मचारी ने किसी तरह एक गेस्ट के मोबाइल फोन से होटल संचालक को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलने पर पुलिस को भी मामले से अवगत कराया गया। सूचना मिलते ही गोमतीनगर पुलिस की टीम होटल पहुंची और मौके से दो संदिग्धों को पकड़ लिया। पुलिस ने उनकी तलाशी ली तो बड़ी संख्या में फर्जी दस्तावेज और पहचान पत्र बरामद हुए।

# गंगा एक्सप्रेसवे पर लगातार तीसरे दिन धंसी सड़क
# 13 किमी में 6 जगह दरारों से निर्माण गुणवत्ता पर उठे सवाल

लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की खामियां अभी थमीं नहीं थी कि गंगा एक्सप्रेसवे धंसने का सिलसिला रुक नहीं रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे पर लगातार तीसरे दिन सड़क धंसने की समस्या सामने आई है। पहले पांच मीटर सड़क धंसी। अब 13 किलोमीटर के दायरे में छह जगह किनारे की सड़क धंसी मिली है। इससे एक्सप्रेसवे की निर्माण गुणवत्ता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे मुख्य मार्ग पर मंगलवार को 13 किमी के दायरे में आधा दर्जन स्थानों पर सड़क धंसने की समस्या पाई गई। मंगलवार को सड़क धंसने की समस्या के साथ अब तक लगातार तीसरे दिन तक जहां एक्सप्रेसवे आठ स्थानों पर धंस चुका है। वहीं गांव सरांय कटियान निकट किमी 421 पर रविवार को व बशीरतगंज गांव के पास किमी 422 के बीच सोमवार को ही रोड धंसी थी। जिस पर ओवर लैपिंग कर डामर का पैच वर्क किया गया था। मंगलवार को इसी स्थान पर मार्ग दोबारा धंस गया और दरारें आ गईं। मंगलवार सुबह हुई तेज बारिश में गंगा एक्सप्रेसवे पर गांव बशीरतगंज निकट किमी 421, सरांय कटियान निकट किमी 422, दरोगा खेड़ा गांव निकट किमी 423 ओरहर गांव निकट किमी 431, रायपुर गांव के पास किमी 432 व खंभार खेड़ा गांव निकट किमी 433 पर सड़क किनारे पर धंस गई है। जहां सड़क धंसी है वहीं ढलान की मिट्टी भी धंसी है। बशीरतगंज टोल से एक्सप्रेस वे पर जाने वाली रोड की मरम्मत एक हफ्ते पहले हुई थी। वहीं एक साथ मार्ग धंसने के बाद बरसात रुकते ही निर्माण एजेंसी की गाड़ियां मजदूरों के साथ मौके पर पहुंची और मरम्मत कार्य शुरू कर दिया। बशीरतगंज के आसपास दर्जनों जगह ऐसी है जहां नालियां टूट चुकी हैं। कंक्रीट की ढलान में दरारें आ चुकी है। गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण में कार्यदाई संस्था पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर की खराब इंजीनियरिंग का परिणाम अब लगातार देखने को मिल रहा है। कई बार मरम्मत के बावजूद रोड और ढलान की मिट्टी धंसने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। जो फिर दरक गई। 421 पर सोमवार को जहां रोड धंसी थी और ढलान की मिट्टी नाली बह गई थी। मंगलवार को उसके बगल मे नाली और कंक्रीट की ढलान करीब 300 मीटर दरक गई। जो किस समय ढह जाएगा कहना मुश्किल है। प्रोजेक्ट मैनेजर आरके मिश्रा ने बताया कि बारिश के दौरान एक्सप्रेसवे के संवेदनशील हिस्सों की लगातार निगरानी की जा रही है। जहां भी सड़क के किसी हिस्से में समस्या सामने आती है, वहां टीमों को तत्काल भेजकर आवश्यक सुधार कार्य कराया जा रहा है। बारिश के मौसम को देखते हुए एक्सप्रेसवे की नियमित पेट्रोलिंग और तकनीकी निरीक्षण बढ़ाया गया है। टीमों को किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, ताकि यात्रियों को सुरक्षित और सुगम सफर उपलब्ध कराया जा सके।गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण के दौरान डंपरों की निकासी के लिए निहालपुर-भदनी नाले की पुलिया के पास मिट्टी भरकर बनाए गए रास्ते से जलनिकासी बाधित हो गई। वर्षा के दौरान पानी न निकलने से करीब दो हजार बीघा धान की फसल जलमग्न हो गई। किसानों ने तहसीलदार अशोक कुमार शुक्ला से शिकायत कर मौके की जांच कराकर कार्रवाई की मांग की है।

## शिव मंदिरों में दिन भर हर-हर महादेव का उद्घोष गुंजायमान

सावन के तीसरे सोमवार पर शिव मंदिरों में दिन भर हर-हर महादेव का उद्घोष गुंजायमान होता रहा। शहर और ग्रामीण अंचलों में स्थित शिव मंदिरों के भोर पहर ही पट खोल दिए गए। दर्शनार्थियों ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए। भक्तों ने शिवलिंग पर बेलपत्र, फूल, भांग, धतूरा आदि चढ़ाकर पूजन-अर्चन किया। मगरवारा स्थित गोकुल बाबा मंदिर में भी शिव पूजन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ा। शहर के बड़े चौराहे स्थित झंडेश्वर, तालिब सराय का झारखंडेश्वर, सिद्धनाथ, शिव नगर का शिव मंदिर, पूरन नगर का गोपेश्वर महादेव, राजाशंकर सहाय स्थित शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ रही। सावन के तीसरे सोमवार पर इन मंदिरों के पट भोर पहर ही भक्तों के लिए खोल दिए गए थे। भगवान शिव के दर्शन के लिए भक्त सुबह से ही मंदिरों में पहुंचने लगे थे। नौ बजे के करीब भीड़ काफी बढ़ गई तो भक्तों की कतारें लग गईं। भक्तों ने शिवलिंग पर जलाभिषेक के साथ दूध, बेलपत्र, फूल, भांग व अन्य सामग्री चढ़ाई और उनका पूजन किया। इसके बाद भक्तों ने भगवान सदाशिव की आरती उतारी। घरों में भी श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ का पूजन-अर्चन किया। शिव चालीसा का पाठ किया। उधर ग्रामीण अंचलों के भी शिव मंदिरों में भीड़ रही। मंदिरों में कतारों में लगे भक्त हर-हर, बम-बम का उद्घोष करते रहे।

## तालाब में मछली पकड़ने के दौरान नाव पलटने से युवक की डूबकर मौत

गंगा एक्सप्रेसवे के लिए पांच बीघा से अधिक में बीस फीट गहराई तक खनन से बने तालाब में मछली पकड़ने के दौरान नाव पलटने से युवक की डूबकर मौत हो गई जबकि साथी बाल-बाल बच गया। पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर जांच की। माखी थाना क्षेत्र के रुपऊ गांव निवासी नफीस (33) सोमवार को गांव के ही साथी खालिक के साथ करीब डेढ़ किमी दूर मझखोरिया के सामने गंगा एक्सप्रेसवे के किमी 415 के पास तालाब में मछली पकड़ने गया था। खालिक ने बताया कि एक्सप्रेसवे निर्माण के दौरान यहां पांच बीघा से अधिक जमीन में मिट्टी का खनन किया गया था। पानी भरने से यह बड़े तालाब का रूप ले चुका है। बताया कि जाल खींचने के दौरान नाव अनियंत्रित होकर पलट गई। इससे दोनों डूबने लगे। खालिक के मुताबिक वह किसी तरह किनारे पहुंचा और निकल आया। शोर मचाने पर आसपास के लोगों को बुलाया और उनकी मदद से नफीस को बचाने का प्रयास किया लेकिन गहराई में जाने से वह डूब गया था। भीड़ में रहे कुछ लोग तैरना जानते थे, उनकी मदद से शव को बाहर निकाला जा सका। नफीस की मौत से पत्नी साजिदा, चार बच्चों अमीना, सोहिल, शिफा और शोएब बेहाल हैं। घटना की सूचना पर पुलिस ने भी घटनास्थल पर जांच की और शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। थानाध्यक्ष योगेश कुमार सिंह ने बताया कि अभी तक किसी ने आरोप नहीं लगाया है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट और तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

## तेज रफ्तार एंबुलेंस आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई दिल्ली से इलाज कराकर लौट रहे मरीज की मौत

उन्नाव जिले में लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर सबलीखेड़ा गांव के बाद तेज रफ्तार एंबुलेंस आगे चल रहे वाहन से टकरा गई। इस हादसे मरीज की मौत हो गई। चार को हल्की चोटें आईं। बताया जाता है कि जिस युवक की मौत हुई है, वह पांच दिन पहले इसी स्थान पर डिवाइडर में कार टकराने से घायल हुआ था। दिल्ली में उपचार के बाद आराम मिलने पर सोमवार को घर जाते समय फिर उसी स्थान पर हादसा हो गया। अयोध्या जिले के थाना रुदौली के गांव रसूलाबाद निवासी राजेंद्र कुमार (45) 12 अगस्त को आगरा जा रहे थे। एक्सप्रेसवे पर बेहटामुजावर थाना क्षेत्र के सबलीखेड़ा गांव के पास डिवाइडर से कार टकरा गई थी। इस हादसे में राजेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए थे। परिजन दिल्ली के अस्पताल में इलाज करा रहे थे। हालत में सुधार होने पर डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया था। सोमवार को परिजन एंबुलेंस से उन्हें लेकर अयोध्या जा रहे थे। एक्सप्रेसवे पर बेहटामुजावर के सबलीखेड़ा गांव के पास तेज रफ्तार एंबुलेंस ट्रक में पीछे से टकरा गई। इससे राजेंद्र कुमार के साथ उनके भाई पंचमलाल (40), राजेंद्र के बेटे शुभम (20), मुकेश (17) और विशाल (15) घायल हो गए। यूपीडा की टीम ने चोटिल लोगों का इलाज किया। राजेंद्र कुमार को सीएचसी भेजा। हालत गंभीर देख उन्हें केजीएमयू भेजा गया। वहां इलाज के दौरान मौत हो गई। भाई पंचम ने बताया कि राजेंद्र दिल्ली के लोहामंडी में मजदूरी करते थे। पति की मौत से पत्नी गुड्डी, मां जगमाता सहित अन्य परिजन बेहाल हैं। बेहटामुजावर थानाध्यक्ष राजकुमार ने बताया कि सोमवार सुबह पहले एंबुलेंस आगे चल रहे वाहन में भिड़ी उसमें एक की मौत हुई। उसी क्षतिग्रस्त एंबुलेंस में दूसरी कार भिड़ गई। उसमें सात लोगों को चोटें आई थीं। सब सही हैं, वाहनों को हटवाया गया है।

## हादसे में बाइक सवार दो दोस्तों की मौत हो गई

मोहान-मियागंज मार्ग पर हसनगंज क्षेत्र में ट्रक को ओवरटेक करने के दौरान बाइक सड़क किनारे बिजली के पोल से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार दो दोस्तों की मौत हो गई। शव देख स्वजन बेहाल हो गए। आसीवन क्षेत्र के कनिगांव निवासी सुरेश का 25 वर्षीय बेटा कमल मंगलवार शाम लगभग छह बजे अपने दोस्त 26 वर्षीय अमित पुत्र विजय सिंह के साथ बाइक से हसनगंज की ओर जा रहा था। मोहान-मियागंज मार्ग पर हसनगंज के निंदेमऊ के पास उन्होंने ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश की। इसी दौरान बाइक अनियंत्रित हो सड़क किनारे लगे बिजली के पोल से टकरा गई। हादसे में दोनों दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने दोनों को सीएचसी पहुंचाया। जांच के बाद डाक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। प्रभारी निरीक्षक शरद कुमार ने बताया कि स्वजन को जानकारी देकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं।

## गंगा का जलस्तर पांच सेंटीमीटर घटने के बावजूद बाढ़ग्रस्त मोहल्लों में मुश्किलें बरकरार

गंगा का जलस्तर सोमवार को पांच सेंटीमीटर घटा, लेकिन पश्चिमी गंगाघाट क्षेत्र के बाढ़ग्रस्त मोहल्लों में लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। गंगा अभी भी चेतावनी बिंदु से 23 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जिससे गंगा किनारे रहने वाले लोगों की चिंता बनी हुई है। गोताखोर, हुसैननगर, मोहम्मदनगर, शाहीनगर और करबला मोहल्लों में 200 से अधिक मकान पानी से घिरे हुए हैं। लोग नाव के सहारे जरूरी काम के लिए बाहर निकल रहे हैं।बाढ़ग्रस्त इलाकों के लोगों का कहना है कि पानी घरों के अंदर तक पहुंचने से विषैले जीव-जंतुओं का खतरा बढ़ गया है। वहीं बिजली आपूर्ति बंद होने के कारण शाम होते ही कई घर अंधेरे में डूब जाते हैं। इससे बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। लोगों ने प्रशासन से बिजली आपूर्ति बहाल करने और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत व्यवस्था बढ़ाने की मांग की है।आवागमन की समस्या को देखते हुए प्रशासन ने पश्चिमी क्षेत्र में 15 सरकारी नावें लगाई हैं। इन नावों के जरिए लोग सुरक्षित स्थानों और बाजार तक पहुंच रहे हैं। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार रविवार शाम छह बजे गंगा का जलस्तर 112.280 मीटर था। सोमवार शाम छह बजे यह पांच सेंटीमीटर घटकर 112.230 मीटर हो गया। हालांकि जलस्तर में मामूली कमी के बावजूद खतरा पूरी तरह टला नहीं है।मिश्रा कॉलोनी, मनोहरनगर, बालूघाट, सीताराम कॉलोनी, शक्तिनगर, इंदिरानगर, गंगानगर, बहादुर बगिया, रविदासनगर और आलमनगर के लोगों की चिंता अभी भी बरकरार है। लोगों का कहना है कि यदि दोबारा बारिश तेज हुई और जलस्तर बढ़ा तो हालात और बिगड़ सकते हैं। क्षेत्रीय लेखपाल प्रशांत अवस्थी ने बताया कि जलस्तर में कमी आई है और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। प्रभावित इलाकों में नावों के साथ राहत एवं निगरानी व्यवस्था पर भी नजर रखी जा रही है।

# राम मंदिर चढ़ावे की रकम मामले में SIT रिपोर्ट चंपत राय-अनिल मिश्रा को क्लीन चिट

**राम मंदिर में चढ़ावे की रकम से जुड़ी कथित चोरी के मामले की जांच कर रही SIT ने अपनी रिपोर्ट श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दी है।रिपोर्ट में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और कोषाध्यक्ष अनिल मिश्रा को मामले में दोषमुक्त बताए जाने की बात सामने आई है।रिपोर्ट के बाद अयोध्या के साधु-संतों और जनप्रतिनिधियों ने संतोष जताया है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में अंतिम रिपोर्ट और आगे की कानूनी प्रक्रिया अहम होगी।**

राम मंदिर में चढ़ावे की रकम से जुड़ी कथित चोरी के मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) ने अपनी रिपोर्ट श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दी है। रिपोर्ट में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और कोषाध्यक्ष अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दिए जाने की बात सामने आई है। SIT की रिपोर्ट पर साधु-संतों और अयोध्या के जनप्रतिनिधियों ने संतोष जताया है।S.I.T की जांच रिपोर्ट में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और कोषाध्यक्ष अनिल मिश्रा को मामले में दोषमुक्त बताया गया है। रिपोर्ट सामने आने के बाद अयोध्या में साधु-संतों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इसे संतोषजनक कदम बताया। राम वल्लभ कुंज के उत्तराधिकारी और राम मंदिर ट्रस्ट की धार्मिक समिति के सदस्य महंत राजकुमार दास ने कहा कि चंपत राय निर्दोष हैं। उन्होंने कहा कि संत समाज पहले से ही सामूहिक रूप से यह बात कहता रहा है कि इस मामले में ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारी दोषी नहीं हैं। महंत राजकुमार दास के मुताबिक, मामले में दोषी पाए गए कर्मचारी जेल में हैं और उन्हें अपने किए की सजा भुगतनी पड़ रही है। तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगद्गुरु परमहंस आचार्य ने भी SIT की रिपोर्ट पर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दी है। उन्होंने दावा किया कि जांच तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर की गई और इसमें किसी तरह का दबाव नहीं था। उनके मुताबिक, निष्पक्ष तरीके से जांच के बाद जो तथ्य सामने आए, उन्हें रिपोर्ट में शामिल किया गया है। परमहंस आचार्य ने कहा कि अयोध्या के साधु-संत और राम मंदिर के प्रति आस्था रखने वाले लोग इस रिपोर्ट से संतुष्ट हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में राम मंदिर की मर्यादा के खिलाफ इस तरह की घटना दोबारा नहीं होगी। उन्होंने कहा कि SIT की जांच में चंपत राय और अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दी गई है। परमहंस आचार्य ने कहा कि चंपत राय को लेकर संत समाज पहले से ही आश्वस्त था कि वह इस तरह के मामले में शामिल नहीं हो सकते। उन्होंने चंपत राय की भूमिका की प्रशंसा करते हुए उन्हें सच्चा सनातनी बताया और कहा कि उनके नेतृत्व में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। अयोध्या के मेयर गिरीश पति त्रिपाठी ने भी S.I.T की रिपोर्ट को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दी गई है। मेयर ने उम्मीद जताई कि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद मामले को लेकर समाज में बने संशय को दूर करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि जांच के जरिए सच्चाई सामने आएगी और स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी। गिरीश पति त्रिपाठी ने जांच की पूरी प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर इस मामले में FIR दर्ज कराई गई थी। इसके बाद ट्रस्ट के ही अनुरोध पर SIT का गठन किया गया और जांच के बाद उसी क्रम में रिपोर्ट ट्रस्ट को सौंप दी गई। अयोध्या के मेयर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने SIT को अपनी अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। ऐसे में ट्रस्ट को सौंपी गई मौजूदा रिपोर्ट के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जांच की प्रक्रिया में किसी भी दोषी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

## केंद्र सरकार और सत्ताधारी दल पर तीखा हमला

v कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सहारनपुर से केंद्र सरकार और सत्ताधारी दल पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष ने उन्हें 12 साल की नींद से जगा दिया है और अब उन्हें सोने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने संसद में नियमों के अनुसार, बहस कराने और अपनी स्थगन प्रस्ताव स्वीकार करने की मांग दोहराई। इमरान मसूद ने कहा कि हम चाहते थे कि कार्यवाही जारी रहे। हम चाहते थे कि नियमों के अनुसार बहस हो, जिसमें आप हमारे स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करके उस पर चर्चा कराते। हम यहां उनके भाषण सुनने नहीं आए हैं। संसद नियमों के अनुसार चलती है। हमने बार-बार आग्रह किया कि हमारे स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार कर कार्यवाही जारी रखें... हमने उन्हें 12 साल की नींद से जगाया है; अब आपको सोने नहीं देंगे। अब जाग जाइए। उन्होंने स्पष्ट किया कि विपक्ष संसद को बाधित करने के लिए नहीं, बल्कि नियमों के तहत मुद्दों पर चर्चा के लिए आया है। सहारनपुर में दिए गए बयान में मसूद ने सरकार पर बच्चों के खिलाफ बल प्रयोग का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए। आप बच्चों पर लाठियां चला रहे हैं; बच्चों पर पैलेट गन चला रहे हैं। बिहार में आपकी सरकार बच्चों पर सीधे एके-47 चला रही है। आपको शर्म आनी चाहिए। आपने इस देश का क्या हाल कर दिया है। उन्होंने इन घटनाओं को लोकतंत्र और मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया। राम मंदिर दान मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा को एसआईटी द्वारा क्लीन चिट दिए जाने पर इमरान मसूद ने व्यंग्य किया। उन्होंने कहा कि उन्हें क्लीन चिट दी गई, हर चीज में उन्हें क्लीन चिट मिलनी ही थी। उनका इशारा सत्ता पक्ष के लोगों को आसानी से राहत मिलने की ओर था।

## बसपा नेता आतिफ खां की दो मंजिला मार्केट पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई

बदायूं जिले के दातागंज में पीडब्ल्यूडी (लोक निर्माण विभाग) की भूमि पर अवैध कब्जा कर बनाई गई दो मंजिला मार्केट पर मंगलवार को बुलडोजर से कार्रवाई की गई। पीडब्ल्यूडी की टीम ने बुलडोजर से मार्केट की 14 दुकानों को ध्वस्त कर दी। इस दौरान भाजपा विधायक राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू की दुकान की सीढ़ियों पर भी बुलडोजर चला। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान दातागंज इंस्पेक्टर भारी फोर्स के साथ मौके पर तैनात रहे। नगर पालिका दातागंज के ईओ और पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता अभिषेक कुमार भी मौके पर डटे रहे। बताते हैं कि कई साल पहले यह दुकानें पीडब्ल्यूडी की भूमि पर अवैध रूप से बनाई गई थीं। इन अवैध दुकानों पर बुलडोजर कार्रवाई के आदेश पहले ही हो चुके थे, लेकिन फोर्स नहीं मिलने की वजह से कार्रवाई रुकी थी। मंगलवार को फोर्स मिलने पर पीडब्ल्यूडी ने दुकानों को ध्वस्त कर दिया। सहायक अभियंता अभिषेक कुमार ने बताया कि साल 2005 में आतिफ खां ने ये दुकानें बनवाई थीं। नगर पालिका से नक्शा बनवाया गया था, तब नगरपालिका ने उस पर यह लिख दिया था कि पीडब्ल्यूडी की अनुमति भी जरूरी है, पीडब्ल्यूडी से अनुमति लेने के बाद नक्शा मान्य माना जाएगा लेकिन पीडब्ल्यूडी से अनुमति नहीं ली गई थी। आतिफ खां कांग्रेस और सपा में नेता रहे। मौजूदा समय में बसपा के मंडल अध्यक्ष हैं। निर्माण के दौरान नोटिस जारी किए गए थे। अब बुलडोजर कार्रवाई हुई है।

## सीतापुर में कांग्रेस को कार्यालय खाली करना होगा

उत्तर प्रदेश के सीतापुर में कांग्रेस को कार्यालय खाली करना होगा। नगर पालिका ने कांग्रेस को दफ्तर खाली करने के लिए 15 दिन का समय था। नगर पालिका के आदेश को कांग्रेस ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में चुनौती दी और स्टे लगाने की मांग की। हाई कोर्ट ने कांग्रेस नगर अध्यक्ष की अपील खारिज कर दी और बेदखली आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साल 1971 से इस कार्यालय पर कांग्रेस का कब्जा है। आरोप है कि कांग्रेस ने पिछले 55 सालों से एक भी रुपये किराया जमा नहीं किया है। नजूल की जमीन पर बिना आवंटन के यह कार्यालय चल रहा था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि सरकारी ज़मीन पर लंबे समय से कब्ज़ा होने से वह कब्ज़ा कानूनी नहीं हो जाता। साथ ही, कोर्ट ने यह भी नोट किया कि याचिकाकर्ता ऐसा कोई अलॉटमेंट ऑर्डर या दूसरा दस्तावेज़ पेश नहीं कर पाए जिससे यह साबित हो सके कि प्रॉपर्टी उन्हें कानूनी तौर पर अलॉट की गई थी। जस्टिस आलोक माथुर और जस्टिस अमिताभ कुमार राय की बेंच ने कांग्रेस कमेटी, सीतापुर की ओर से दायर रिट याचिका पर यह आदेश दिया। याचिका में नगर पालिका परिषद, सीतापुर के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (इन-चार्ज) के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें टैमसेन गंज इलाके में प्लॉट नंबर 244/1 से जुड़े रिकॉर्ड से याचिकाकर्ताओं के नाम हटाने और उन्हें प्रॉपर्टी से बेदखल करने का निर्देश दिया गया था।याचिकाकर्ताओं का दावा था कि 1971 से सीतापुर में घंटा घर के ऊपरी हिस्से पर उनका कब्ज़ा था और उन्होंने 1971 में 320 रुपये किराया चुकाने की रसीद भी पेश की। हालांकि, कोर्ट ने पाया कि पिछले 55 सालों से कोई किराया नहीं दिया गया था और याचिकाकर्ता ऐसा कोई एग्रीमेंट, अलॉटमेंट लेटर या दूसरा दस्तावेज़ पेश नहीं कर पाए जिससे प्रॉपर्टी के कानूनी अलॉटमेंट या कब्ज़े की पुष्टि हो सके। राज्य सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि प्रॉपर्टी 'नज़ूल' ज़मीन थी और उस पर कब्ज़ा गैर-कानूनी था।